शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

फीस के अभाव में बच्चों को परीक्षा से वंचित न किया जाए

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से स्कूल खोलने की मांग की जा रही है वहीं पालक महासंघ स्कूल खोलने का विरोध कर रहा है। महासंघ का कहना है कि पहली से आठवीं तक के स्कूल बिल्कुल नहीं खोले जाएं। साथ ही फीस के अभाव में बच्चों को परीक्षा से वंचित न किया जाए। इसी संदर्भ में शुक्रवार को पालक महासंघ और माय पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्तजयश्री कियावत से मिलने पहुंचे। पालक महासंघ ने फीस से संबंधित मांगपत्र सौंपा।

उन्होंने मांग की है कि स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। स्कूलों का सत्र लगभग समाप्त हो चुका है। स्कूलों द्वारा केवल फीस प्राप्त करने के लिए शासन पर स्कूल खोलने का दबाव बनाया जा रहा है। पालक महासंघ ने शासन से निवेदन किया है कि इस वर्ष पहली से ग्यारहवीं तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। बारहवीं के बच्चों को सिर्फ परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए। सभी स्कूलों को निर्देशित किया

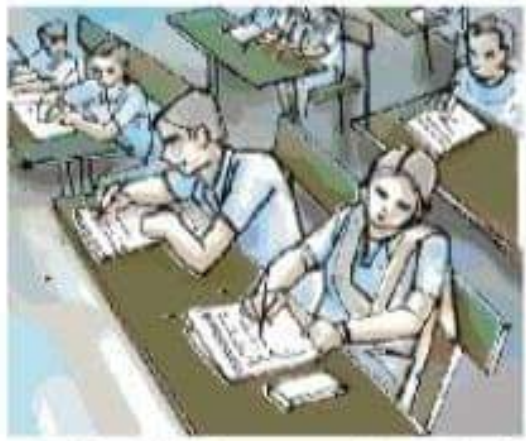

जाए कि फीस के अभाव में बच्चों को ऑनलाइन कक्षा, बोर्ड के पंजीयन और परीक्षा से वंचित न किया जाए। शिक्षण शुल्क को परिभाषित किया जाए। इस वर्ष फीस वृद्धि स्थगित की जाए। किस्तों में फीस देने की सुविधा प्रदान की जाए। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि पहली से आठवीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फीस के संबंध में कहा कि स्कूलों को मप्र शासन एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही फीस लेनी होगी।

> निजी स्कूल सिर्फ फीस लेने के लिए दो माह के लिए स्कूल खोलना चाह रहे हैं जबकि कोरोना काल में बच्चों को स्कूल बुलाना सही नहीं है।
> **कमल विश्वकर्मा**, अध्यक्ष, पालक महासंघ

शिक्षिका सह सहायक वार्डनों का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग

भोपाल। कर्मचारी आयोग के सदस्य वीरेंद्र खोंगल ने आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स को एक पत्र लिखा है। जिसमें 24 घंटे ड्यूटी करने वाली शिक्षिका सह सहायक वार्डनों का ग्रेड पे को संशोधित करने की मांग की गई है। खोंगल ने बताया कि हर वार्डन पर हॉस्टल में रहने वाले 50 से 100 छात्रों की जिम्मेदारी रहती है। उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है। वार्डनों की योग्यता स्नातक व बीएड है। उन्हें पढ़ाने के अलावा भी अन्य कार्य करने पड़ते हैं। अधिक कार्य को देखते हुए 3200/2800/2400 रुपये ग्रेड पे के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाए।

नौ सेंटर पर 1560 ने दी जेल प्रहरी बनने की परीक्षा

ग्वालियर (नईदुनिया रिपोर्टर)। मप्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को जेल प्रहरी की परीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण 24 दिसंबर को आयोजित होगा। परीक्षा जेल मुख्यालय भोपाल के अंतर्गत संचालित हो रही है। प्रथम चरण में तीन हजार 120 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इनमें से 1560 परीक्षार्थी तय सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। सभी प्रतिभागियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ा। किसी भी प्रतिभागी को बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्हें छह-छह फीट की दूरी पर बनाए गए गोलों में खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो किसी भी सेंटर पर कोई बीमार प्रतिभागी

सामने नहीं आया। सभी का तापमान सामान्य था।

दो पालियों में पूरा हुआ पेपर का चरण: पहले चरण में पेपर आनलाइन मोड पर हुआ। इसकी दो पालियां रखी गईं। कोविड के कारण दोनों ही पालियों को विशेष ढंग से डिजाइन किया गया। प्रथम पाली की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शुरू हुई। यह प्रतिभागियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम था। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए उन्हें सुबह 8:30 से 9 बजे तक का समय दिया गया। इसके बाद उन्होंने परीक्षा दी। दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम रखा गया। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दोपहर 1:50 बजे से 2 बजे तक रखा गया। इसके बाद पाली दो से शाम पांच बजे तक चली।

इन केंद्रों पर हुई परीक्षा: एमिटी यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट रोड़, सर्वधर्म शिक्षा महाविद्यालय चितौरा रोड़, जीआर नर्सिंग कालेज रायरू, मालवा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट, बथेस्डा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस, माधव महाविद्यालय और लक्ष्मी नारायण कालेज आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस में जेल प्रहारी की परीक्षा हुई।

तीन हजार रुपये फीस में कराया जा रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स

डीएवीवी में 14 दिसंबर से शुरू होगा शॉर्ट टर्म कोर्स

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कोरोना महामारी में विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत देने जा रहा है। विद्यार्थियों को मात्र तीन हजार रुपये में कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कराया जा रहा है। इसके तहत कार्यालय में काम आने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सल और अन्य सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे। कोर्स की शुरुआत 14 दिसंबर से हो रही है, जो एक जनवरी 2021 तक संचालित होगा।

इसमें प्रवेश लेने के लिए 12 दिसंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आवेदन करने के पहले रजिस्ट्रार रेगुलर कोर्सेस डीएवीवी इंदौर के नाम से तीन हजार रुपये की राशि एनइएफटी करनी होगी। इसकी रसीद आवेदन फॉर्म के साथ देनी होगी।

शाम को लगेगी कक्षाएं, विद्यार्थी के पास कंप्यूटर होना जरूरी: विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र द्वारा संचालित किए जा रहे कोर्स में रोजाना दो घंटे कक्षाएं लगेंगी। शाम चार से छह बजे तक विद्यार्थी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से सीख सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। इसके लिए प्रवेश लेने विद्यार्थियों के पास लेपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होना जरूरी है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश लेने के नियमों में कहा है कि किसी भी उम्र के प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र द्वारा कोरोना महामारी के कारण युवाओं की स्कील वेहतर करने के लिए और भी कोर्स संचालित किए जाते रहे हैं। अधिक जानकारी वेबसाइट https//www.dauniv.ac.in से ले सकते हैं।

रेलवे भर्ती परीक्षा 15 से, मास्क लगाना अनिवार्य

नई दिल्ली। रेलवे में 1.40 लाख पदों को भरने के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। भर्ती परीक्षाओं में आवेदक को साधारण मास्क पहनकर जाना होगा। उनके लिए परीक्षा केंद्र कम से कम यात्रा समय को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने डिजाइनर या गैर-मानक के मास्क पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है।

कम छात्र संख्या होने की वजह से विवि ने लिया फैसला

अग्रणी कॉलेजों और महाविद्यालयों को मिली ओपेन बुक परीक्षा की जिम्मेदारी

स्टार समाचार | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने आगामी ओपेन बुक परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए आयोजन की जिम्मेदारी लीड कॉलेज और स्थानीय कॉलेजों को दी है। कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष को पत्र लिखकर यह कहा है कि छात्र संख्या कम होने के कारण यह परीक्षायें जिला स्तरीय या अग्रणी महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी। न की विश्वविद्यालय में।

गौरतलब है कि सितम्बर माह में

आयोजित हुई स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में जो छात्र शामिल होने से वंचित रह गए थे। उनके हित को देखते हुए विश्वविद्यालय ने वंचित छात्रों को दूसरा मौका देने का फैसला लिया है। जिसमें सतना, सीधी, बैढ़न, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और रीवा के छात्र शामिल हो सकेंगे। मगर इस परीक्षा का आयोजन अपने स्तर से नहीं करेगा बल्कि कॉलेज और लीड कॉलेज को उत्तर पुस्तिका कलेक्शन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी संभालनी होगी और नियत समय पर परीक्षा परिणाम के लिए विश्वविद्यालय को अंक भेजने होंगे।

कॉलेजों में असमंजस

कुलपति के लिखे पत्र से सरकारी कॉलेजों और प्राइवेट कॉलेजों में असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल परीक्षायें ओपेन बुक पद्धति की परीक्षा आयोजित करानी है। जिसके लिए छात्रों को एसआई डी में प्रश्न पत्र मुहैया कराना होगा। मगर अब तक प्रश्न पत्र तैयार नहीं हुए है न ही पुराने प्रश्न पत्र हटाये गये है। कॉलेजों को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या उन्हें खुद से प्रश्न पत्र तैयार करने है या विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र अपलोड करेगा। बता दें कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा ही प्रश्न पत्र पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। क्योंकि हर कॉलेज अपना अलग प्रश्न पत्र बनाये और उसे अपलोड करें। यह संभव नहीं हो पाएगा।

स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए सिर्फ टीसी व माइग्रेशन जरूरी

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को सिर्फ स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) और माइग्रेशन का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। यह आदेश प्रदेश के सभी कॉलेजों को भेज दिए गए हैं।

दरअसल, ये शिकायतें मिली थीं कि कॉलेजों में विद्यार्थियों से अन्य प्रमाण पत्र (आय-जाति आदि) भी मांगे जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। विभाग की ओर से कहा गया है कि दो दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों ने अन्य प्रमाण पत्र पहले की कक्षाओं में जमा किए हैं। यह भी सुविधा दी गई है कि जिनके पास टीसी और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं हैं, वे शपथ पत्र देकर एक माह में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुविधा

- **कॉलेजों की ओर से अन्य दस्तावेज मांगने की शिकायत आदेश हुए जारी**
- **टीसी व माइग्रेशन नहीं होने पर शपथ पत्र देने की छूट**

लाखों विद्यार्थियों का प्रवेश करना है सुनिश्चित : 19 दिसंबर तक प्रदेश के पांच लाख 61 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित (कंफर्म) करना है। यही अंतिम तारीख टीसी और माइग्रेशन जमा करने की भी है। इन्हें जमा करने पर ही उनका प्रवेश कंफर्म हो जाएगा। विद्यार्थियों की शिकायत थी कि कॉलेजों की ओर से जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, उन्हें बनवाने में समय लग रहा है। प्रवेश की अंतिम तारीख नजदीक होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन शिकायतों पर सभी प्राचार्यों के लिए निर्देश जारी किए और इस पर अमल सुनिश्चित करने को कहा।

> सभी कॉलेजों को टीसी और माइग्रेशन के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी आदेश भेज दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। विद्यार्थी शपथ पत्र देकर एक माह का अतिरिक्त समय ले सकते है।
>
> **चंद्रशेखर चिलम्बे**, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

SCHOOL OF ECO
DEVI AHILYA VI

आयुर्वेद पांच हजार साल पहले सर्जरी कर चुका, एमबीबीएस, एमएस जैसे कोर्स भी : एनआईएमए

इधर, नेशनल इंटीग्रेटेड एंड मेडिकल एसोसिएशन (एनआईएमए) के स्टेट प्रेसीडेंट डॉ. महेश गुप्ता का कहना है हमारे डॉक्टर पहले से अपेंडिक्स सहित अन्य सर्जरी कर रहे हैं। हमें 300 तरह की सर्जरी करने का अधिकार था। कानूनी मामलों में परेशानी आती थी, जिसके लिए अब सरकार नोटिफिकेशन लेकर आई है। किडनी ट्रांसप्लांट तक कर रहे हैं। आईएमए ने आपत्ति ली, इसलिए इसे स्पष्ट कर दिया गया है। पांच हजार वर्ष पूर्व सुश्रुत द्वारा सर्जरी की गई थी। अब उन्हीं सारे औजारों का मॉडर्नाइजेशन किया गया है। सभी तरह की सर्जरी के गुरु आयुर्वेद से निकले थे। एलोपैथी डॉक्टर तो सौ साल से सर्जरी कर रहे हैं। आज यह विरोध कर रहे हैं कि सर्जरी की अनुमति क्यों दी जा रही है, जबकि हमारे बीएएमएस की तरह आयुर्वेद में भी एमएस की पढ़ाई भी करवाई जाती है। ईएनटी, आंखों, हड्डी सहित कई विधाओं में शल्य चिकित्सा सिखाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में आयुर्वेदिक चिकित्सक जनरल सर्जरी कर रहे हैं। सिर्फ मप्र ही इस मामले में थोड़ा पिछड़ा है। एमबीबीएस और एमएस या एमडी की तरह हमारे भी पाठ्यक्रम हैं। हमारे पांच साल के पाठ्यक्रम में एनोटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद विशेषज्ञता वाली ब्रांच में पढ़ाई करवाई जाती है। हमारे कई लोगों ने बीएएमएस करने के बाद एलोपैथी में भी पढ़ाई की है और कई एमबीबीएस डॉक्टरों ने आयुर्वेद में एमडी किया है। उनकी यह आपत्ति सही है, लेकिन एक ही आयुर्वेदिक चिकित्सक सभी ऑपरेशन नहीं करेगा। उसके लिए अलग-अलग ब्रांच होगी। उसी अनुसार ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षण मिलेगा।

एनआईओएस: बोर्ड परीक्षाएं अगले माह

सिटी रिपोर्टर | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे के बीच होंगी।

जेयू... शोध छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति, 30 तक मांगे आवेदन

ग्वालियर | जीवाजी यूनिवर्सिटी से विज्ञान, जीवविज्ञान, समाज विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंध, विधि, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा गृह विज्ञान में शोध करने वाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए इसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। ये छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग के ऐसे छात्रों को दी जाएगी, जिन्होंने स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही यूनिवर्सिटी में वह पीएचडी के लिए पंजीकृत होना चाहिए। पुनः पंजीयन करने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे।

शिक्षकोत्सव : शिक्षक किताबी ज्ञान के साथ-साथ अपने आचरण से भी विद्यार्थियों को शिक्षित करता है -डॉ. पंड्या

आंतर भारती, पुणे के राष्ट्रीय शिक्षकोत्सव में शहर के प्राध्यापक ने रखे विचार

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

ऐसा नहीं है कि शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान से ही शिक्षा देता है, बल्कि शिक्षक अपने आचरण से भी विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। वह पाठ्यक्रम के विषयों का पाठ तो किताबों से पढ़ा सकता है किंतु विद्यार्थियों को धैर्यवान, सहनशील और सहज रहने का पाठ तो स्वयं के आचरण से ही पढ़ा सकता है।

शिक्षक की वेशभूषा और भाषा में संयम की अपेक्षा तो हमेशा की जाती रही है, किंतु अब बात शिक्षक के डिजिटल व्यक्तित्व तक पहुंच गई है। आज शिक्षण एक डिजिटल दौर में प्रवेश कर रहा है और प्रत्येक शिक्षक से कई-कई विद्यार्थी सोशल मीडिया पर भी जुड़े होते हैं, इसलिए अब शिक्षक से यह अपेक्षा भी की जाती है कि उसके द्वारा सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पोस्ट में भी सादगी और संदेश हो। शहर के गणित विषय के प्राध्यापक डॉ. गिरीश पंड्या ने आंतर भारती, पुणे की अगुवाई में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षकोत्सव में प्रमुख वक्ता के रूप में यह बात कही। डॉ. पंड्या ने कहा यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह समझा सकता है कि आग कैसे उत्पन्न होती है तो वही शिक्षक विद्यार्थियों को यह भी समझाए कि उस आग का उपयोग किसी का घर जलाने में नहीं करना है, बल्कि किसी के घर का चूल्हा जलाने में करना है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सामाजिक दायित्व का बोध भी अवश्य करवाएं ताकि विद्यार्थी में यह भावना आए कि वह इंजीनियर इसलिए नहीं बनना चाहता है कि उसको पैकेज अच्छा मिलेगा बल्कि वह इंजीनियर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह अपने कौशल से सामाजिक निर्माण में भूमिका निभाने वाला है। वह डॉक्टर इसलिए बनना नहीं चाहता है कि मेडिकल लाइन में अधिक पैसा है, बल्कि इसलिए बनना चाहता है कि वह समाज को स्वस्थ करना चाहता है। शिक्षक का दायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों में संवाद की क्षमता उत्पन्न करें, उन्हें जिज्ञासु बनाए, उनमें तर्क करने की क्षमता उत्पन्न करें। समारोह को गुजरात के शिक्षाविद् हर्षद कुमार रावल ने भी संबोधित किया। इस दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविद् ऑनलाइन थे।

रेलवे स्टेशन में बैग सैनिटाइजेशन के नाम पर रोजाना ₹60 हजार की वसूली

एजेंसी का तर्क: हमने रेलवे को दस लाख रुपए दिए हैं, इसलिए ले रहे हैं पैसे

भोपाल • डीबी स्टार

भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैग सैनिटाइज करने के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। इस काम का कांट्रेक्ट लेने वाली एजेंसी के कर्मचारी मुसाफिरों से बैग सैनिटाइज करने के लिए 10 रुपए ले रहे हैं। इस तरह रोजाना लगभग 60 हजार रुपए की एजेंसी को कमाई हो रही है। वहीं रेलवे अफसरों का तर्क है कि यह व्यवस्था वैकल्पिक है। दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन दोनों जगह पर सैनिटाइज करने वाली दो-दो मशीनें लगाई गई हैं। तर्क यह दिया जा रहा है कि सैनिटाइज करने से बैग के बाहर और भीतर मौजूद सभी वायरस समाप्त हो जाएंगे। जबरन बैग सैनिटाइज करने के बदले दस रुपए कांट्रेक्टर द्वारा लिए जाने की कुछ यात्रियों की शिकायत पर डीबी स्टार टीम ने मामले की मौके पर पड़ताल की। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बाहर की तरफ मशीन लगी हुई है। यहां से भीतर जाने वाले यात्रियों से कर्मचारी कहते हैं कि पहले बैग को सैनिटाइज करवाओ। यात्री यह समझकर कि यह व्यवस्था फ्री होगी तो वे अपने बैग मशीन में डाल देते हैं। इसके बाद कर्मचारी उनसे दस रुपए शुल्क मांगते हैं। हालांकि ज्यादातर यात्री यह राशि देने से इंकार नहीं करते, लेकिन कई बार कर्मचारी और मुसाफिर के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर छह पर नजारा अलग है। यहां प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक यात्री को बैग सैनिटाइज करवाना ही होता है। कर्मचारी इसके लिए उन्हें बार-बार जोर देते हैं। जब कोई यात्री बैग सैनिटाइज नहीं करवाता है तो कर्मचारी उससे बहस करने लगते हैं।

अपने ही मास्क का ध्यान नहीं

चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि लाल जैकेट में कंपनी का कर्मचारी पैसे गिनने में मशगूल है। इन्होंने अपना मास्क भी मुंह-नाक के बजाय ठोड़ी पर लटका रखा है। ऐसे में यात्री से बातचीत करना कितना सुरक्षित होगा। हालांकि कुछ मुसाफिर भी बिना मास्क ही नजर आए। स्टेशन परिसर में इन्हें रोकने-टोकने वाला कोई नहीं दिखा।

गणित वसूली का

80 हजार रु. गुरुवार को शाम तक सैनिटाइज कर वसूले गए।

50 हजार रु. औसत रोज के हिसाब से 30 लाख रुपए महीना।

10 लाख रु. रेलवे को (एक बार), 12 लाख की मशीनें, 50 हजार मासिक खर्च। बाकी मुनाफा।

रेलवे ने पैसे लेकर वसूली करने का दिया अधिकार

रेलवे एक मुश्त राशि जमा करवाकर लोगों को सैनिटाइजेशन मशीन लगाने की अनुमति देता है। वर्तमान में लगाई गई मशीन की लागत करीब छह लाख रुपए आई है। एक मशीन पर तीन कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कलेक्टर रेट पर इनको वेतन दिया जाता है। अब कमाई का हिसाब लगाया जाए तो यह इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। खास बात यह है कि ठेकेदार से किए गए अनुबंध में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वह बैग सैनिटाइज कराने का मामला यात्री की इच्छा पर रहेगा।

जबरन वसूली न करें

स्टेशन पर बैग सैनिटाइज करने की मशीन लगाना तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यात्री सैनिटाइज करवाना चाहे। कर्मचारियों का यह कहना कि बैग सैनिटाइज करवाना ही होगा, यह गलत है। जो स्वैच्छिक करवाना चाहते हैं उनके बैग सैनिटाइज करें और उनसे चार्ज ले लें।

हरमीत सिंह, पवन श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह, रामदयाल शास्त्री, रेल यात्री

यह व्यवस्था तो स्वैच्छिक है

स्टेशन पर लगाई गई मशीनों में यात्री स्वेच्छा से बैग सैनिटाइज करवाते हैं। कर्मचारियों के जबरन चार्ज वसूलने की शिकायत हमारे पास नहीं आई है। शिकायत आएगी तो जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे।

उदय बोरवणकर, डीआरएम, पश्चिम मध्य रेलवे मंडल, भोपाल

सीधी बात

राजेश श्रीवास्तव, कांट्रेक्टर, स्ट्रीट वॉल

जबरन वसूली नहीं करते

• रेलवे स्टेशन पर आपकी कंपनी ने ही सैनिटाइज करने वाली मशीनें लगाई हैं?
-हां, वे मशीनें हमने ही लगाई हैं।

• यात्रियों की शिकायत है कि जबरन बैग सैनिटाइज करवाने का दबाव बनाते हैं?
-ऐसा नहीं है, एक बार तो कहना ही पड़ता है।

• यहां की कमाई का क्या हिसाब है?
- एकमुश्त राशि रेलवे को दी है। मशीन के मेंटेनेंस और स्टाफ के वेतन-भत्तों पर भी खर्च होता है। हम दस रुपए शुल्क ले रहे हैं।

ओपन स्कूल की 5वीं-8वीं की परीक्षाएं 14 से, ऑनलाइन मिलेंगे प्रवेश पत्र

उज्जैन। ओपन स्कूल पद्धति से आयोजित होने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 14 दिसंबर से शुरू होंगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट www.mpsos.nic.in पर उपलब्ध है। सहायक संचालक परीक्षा ने बताया विद्यार्थियों के प्रवेश-पत्र एमपी ऑनलाइन पर ओपन स्कूल की वेबसाइट पर एक दिसंबर से उपलब्ध करवा दिए हैं। विद्यार्थी अपनी आईडी डालकर प्रवेश-पत्र निकाल सकेंगे। भोपाल और रतलाम जिले को छोड़कर सभी जिलों में विद्यार्थी संकलन केंद्र पर ही परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से रहेगा।

विद्यालय में 10 प्रतिशत अभिभावकों ने ही जमा किए सहमति-पत्र

कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल नहीं आ रहे विद्यार्थी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मंडीदीप

नगर में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के समय से शासन ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन 6 महीने बाद जब इन्हें खोलने के आदेश दिए तो अभी तक सिर्फ 10 प्रतिशत बच्चों के अभिभावकों ने ही सहमति पत्र स्कूल भेजे हैं और बच्चों को भी स्कूल भेजकर पढ़ाई करवा रहे है, लेकिन 90 प्रतिशत अभिभावक अभी भी कोरोना संक्रमण के डर से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं।

एक ओर जहां शासन की गाइडलाइन के तहत निजी व शासकीय स्कूलों के प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम तो किए हैं, लेकिन संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलने के डर के कारण अभिभावकों ने सहमति-पत्र नहीं भेजे हैं। वहीं निजी स्कूल संचालक भी फिलहाल ऑनलाइन कक्षाओं को प्राथमिकता देकर विद्यार्थियों के अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वे स्कूल फीस लेकर बच्चों की रोजाना ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहें हैं, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो और समय की बचत भी की जा सके। शासन ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी अभी अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने पर अपनी सहमति नहीं दी है।

नए एडमिशन में आई कमी

स्कूल खुलने के 10 दिन बाद स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और वर्तमान व्यवस्था की पड़ताल की तो सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि निजी व शासकीय स्कूलों में नए एडमिशन न के बराबर हुए हैं। वहीं जो छात्र पहले कक्षा 11वीं में था और अब उत्तीर्ण होकर 12वीं में आ गया है ऐसे छात्रों ने भी अभी तक प्रवेश नहीं लिया है। शासकीय बालक हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य अनिता चौधरी ने बताया कि वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक 622 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 20 बच्चे ही आंशिक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। यही नहीं इस वर्ष कक्षा 9 में 100 बच्चों ने कम एडमिशन लिया है।

नगर में बढ़ रहे कोरोना के मरीज फिर भी लोग नहीं लगा रहे मास्क

नगर में बिना मास्क के लोग दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी है मास्क लगाना, जिसको लेकर व्यापारी महासंघ नगर में मास्क बांट रहे हैं और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है उसे मास्क पहना रहे हैं, ताकि अगली बार बिना मास्क के घर से बाहर न निकले, साथ ही उसको समझाइश भी दे रहे हैं। इसके बाद भी कुछ लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बदीसिंह चौहान का कहना है कि सभी वर्ग के लोगों को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मास्क ही वैक्सीन है। हमें अपने आसपास के लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। इधर, विनोद जैन समाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि कई उद्योगों में भी बिना मास्क के कर्मचारी काम करते देखे गए हैं। उन्हें समझाई देने के बावजूद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि वर्तमान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हमे इससे बचने के लिए मास्क लगाना बहुत आवश्यक है।

पारदर्शिता से डर क्यों? • अब तक नहीं आई विवि की प्रवेश सूची, विद्यार्थी हो रहे परेशान

छात्रों... अपना स्टेटस देखते रहो, क्योंकि विवि में व्यक्तिगत सीट हो रहीं आवंटित

यूजी-पीजी के 18 विभागों के छात्रों के स्टेटस हुए अपडेट

भास्कर संवाददाता | सागर

अगर आपने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के बाद ऑनलाइन पंजीयन कराया है तो उसी पर अपना स्टेटस भी चेक करते रहिए। दस्तावेजों के सत्यापन और मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र पाए जाने वाले विद्यार्थी का स्टेटस गुपचुप तरीके से विश्वविद्यालय एडमिशन सेल द्वारा इसी पर अपडेट किया जा रहा है। जिसमें लिखा आ रहा है कि सीट आवंटित कर दी गई है। यूजी-पीजी के करीब 18 विभागों के विद्यार्थियों की सीट आवंटित कर दी गई हैं।

हालांकि यह अलग बात है कि इसका न तो मैसेज विद्यार्थी के मोबाइल पर भेजा जा रहा है और न ही मेल के माध्यम से कोई सूचना दी जा रही है। इतना ही नहीं इस प्रकार की कोई प्रक्रिया चल भी रही है उसकी जानकारी भी विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वेबसाइट तक पर अपडेट नहीं की गई है। यानी विद्यार्थी का यह स्वयं का दायित्व है कि वह इस बात का अंदाजा लगाए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण एडमिशन सेल के विद्वानों ने ऐसा भी कोई नियम बनाया होगा कि छात्रों को स्वयं ही अपना स्टेटस चेक करना होगा।

बहरहाल जो प्रवेश सूची 9 दिसंबर को जारी होना थी, वह 11 दिसंबर को भी जारी नहीं हो सकी। यह कब तक जारी होगी? इस सवाल के जवाब में एडमिशन सेल के चेयरमैन प्रो. एपी मिश्रा ने बताया कि इसकी जानकारी या तो विवि प्रशासन दे सकता है या फिर मीडिया अधिकारी से पूछिए। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि एडमिशन सेल पहली बार लागू की गई ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, छात्रों की मदद के लिए एडमिशन सेल ने जो लैंडलाइन नंबर जारी किया है, उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है।

छात्र बोले-पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल

छात्र सौरभ देव पांडेय, आदित्य सोनी, राघवेंद्र जड़िया, कौस्तुभ पचौरी आदि ने बताया कि हम लोग एडमिशन सेल गए तब कहा गया कि आप लोग स्टेटस चेक करते रहिए, हमारी तरफ से इसकी कोई सूचना मैसेज या मेल से नहीं भेजी जा रही है। सिर्फ फीस भरने के लिए मैसेज भेजेंगे। छात्रों का आरोप है कि इससे पारदर्शिता पर भी सवाल लग रहे हैं।

एडमिशन सेल आज करेगी सूची जारी

एडमिशन सेल द्वारा जानकारी दी गई है कि शनिवार को वर्गवार प्रवेश-सूची विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जो सभी छात्र देख सकेंगे।

-प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, मीडिया अधिकारी, सागर विश्वविद्यालय

21 हजार में से 16338 ने जमा किए दस्तावेज

सागर | छतरपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया में अब 19 दिसंबर तक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। जिले के 18 शासकीय कॉलेजों में करीब 21 हजार विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। अब इन सभी के दस्तावेज जमा करने का काम चल रहा है। शुक्रवार तक सभी कॉलेजों में 16 हजार 338 विद्यार्थी अपने दस्तावेज जमा करा चुके थे। अभी भी करीब 4700 विद्यार्थी ऐसे रह गए हैं जिनको दस्तावेज जमा कराना है। चूंकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे ही में इन 4700 विद्यार्थियों के लिए 8 दिन का समय और मिल गया है। जिला ऑनलाइन एडमिशन के नोडल प्रभारी डॉ. विनय शर्मा ने बताया कि सभी जगह सोशल डिस्टेंस के माध्यम से दस्तावेज जमा करवाए जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के पास टीसी माइग्रेशन नहीं है तो वो शपथ-पत्र भी जमा कर सकते हैं।

पीजी में नया ट्रेंड • 10 कॉलेज में कुल 5801 सीटें, 5012 सीटें हो गई फुल

ओपन बुक में पास होना आसान, पहली बार 86.39% सीटें भरीं

भास्कर संवाददाता | सागर

जिले के शासकीय कॉलेजों में इस बार स्नातकोत्तर में पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में एडमिशन लिए हैं। पूर्व के वर्षों में जहां 65 से 70% सीटें ही फुल हो पाती थीं, जबकि इस बार 86.39% सीटों पर एडमिशन हुए हैं।

इसकी मुख्य वजह विद्यार्थियों से लेकर एक्सपर्ट तक कोरोना के चलते पढ़ाई और परीक्षा के तरीके में आए बदलाव को बता रहे हैं। कोरोना के चलते जहां ओपन बुक एग्जाम शुरू हुए हैं, जिसमें विद्यार्थी घर बैठे ही परीक्षा दे सकता है। जिसमें अच्छे नंबरों से पास होने की संभावनाएं हैं। वहीं कक्षाएं भी अब कॉलेज की जगह ऑनलाइन माध्यम से घरों से ही लग रही हैं। ऐसे में विद्यार्थी कोरोना के समय का उपयोग अपनी डिग्री की योग्यता बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरा कारण यह भी है कि पिछले 8 माह से कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं निकली है। कोचिंग क्लासेस भी ऑनलाइन ही लग रही हैं, जिनमें कम ही संख्या में विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में खाली निकल रहे समय में कई विद्यार्थी स्वयं को स्नातक से अब स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बनाने में लग गए हैं। पीजी में दाखिला लेने वाले छात्र सौरभ ने बताया अभी जॉब निकलने की उम्मीद कम ही है, इसीलिए खाली समय में योग्यता बढ़ाने पीजी में दाखिला ले लिया। छात्र शुभम तिवारी का कहना है कि जॉब की तैयारी कर रहा था। 8 माह से निकली ही नहीं। इसीलिए यूजी करने के एक साल बाद अब पीजी में ही एडमिशन ले लिया है।

जिले के कॉलेजों में प्रवेश की ऐसी है स्थिति

जिले में कुल 18 शासकीय कॉलेज है जिनमें से 10 में ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। इन 10 कॉलेजों में स्नातकोत्तर में कुल 5801 सीटें हैं, जिनमें से 5012 सीटों पर विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। सबसे ज्यादा रुझान कला संकाय की ओर है।

स्नातकोत्तर में संकायवार यह है दाखिले की स्थिति

संकाय	कुल सीट	एडमिशन	प्रतिशत
कला	3541	3132	88.44%
कॉमर्स	800	624	78%
विज्ञान	1344	1149	85.40%
होम साइंस	116	107	92.20%
कुल	5801	5012	86.39%

एक्सपर्ट व्यू • ## ऑनलाइन पढ़ाई के कारण पीजी में रुझान बढ़ा

नौकरियों में विषय विशेषज्ञता की मांग के चलते विद्यार्थी पीजी की डिग्री कर रहे हैं। ऑनर्स कोर्स की भी जिले स्तर पर कमी है, इस कारण भी पीजी की ओर छात्र बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और ओपन बुक एग्जाम का फायदा उठाने भी विद्यार्थी पीजी में एडमिशन ले रहे हैं। एक कारण यह भी है कि वर्तमान में नौकरियां भी ज्यादा नहीं निकल रही हैं, जिसके चलते विद्यार्थी यूजी के बाद ड्रॉप लेकर जॉब की तैयारी शुरू कर देते थे। कई ऐसे भी हैं, जो रुटीन में बने रहने पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं।

- डॉ. नीलिमेश वर्मा,

पूर्व जिला नोडल प्रभारी ऑनलाइन प्रवेश

भर्ती परीक्षा : कोरोना का डर, 2070 को देनी थी परीक्षा, पहले ही दिन 44 फीसदी अनुपस्थित

भास्कर संवाददाता | सागर

जेल प्रहरी के 300 पदों के लिए शुक्रवार से शहर के 6 केन्द्रों पर परीक्षा शुरू हुई। कोरोना के दौर में पिछले 10 माह बाद कोई भर्ती परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा पर कोरोना का असर रहा। डर की वजह से 44 फीसदी आवेदक परीक्षा देने ही नहीं आए। शहर के 6 केन्द्रों पर होने वाली इस परीक्षा में शुक्रवार को 2070 आवेदक को शामिल होना था। लेकिन इनमें से 913 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 1157 आवेदकों ने ही परीक्षा दी। सबसे ज्यादा मकोनिया स्थित नोबल कॉलेज परीक्षा केन्द्र पर 268 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कोरोना के दौर में हो रही परीक्षा के लिए सभी केन्द्रों पर मास्क व सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है।

चतुर्थ सेम के विद्यार्थियों को पेपर देने का दूसरा मौका

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों को ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से परीक्षा देने का दूसरा मौका दिया है, जो पहली बार में परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। जेयू 16 दिसंबर को वेबसाइट पर पेपर अपलोड करेगी। 17 से 20 दिसंबर के बीच पेपर हल करके 21 से 22 दिसंबर तक कापियां कलेक्शन सेंटर पर जमा करनी होंगी। कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस बार परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं। स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों की ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा कराई थी, शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, लेकिन स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के कई विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे -नप्र

आयुर्वेद डाक्टरों को आपरेशन करने की मंजूरी देने का विरोध

ग्वालियर। आयुर्वेदिक डाक्टरों को शासन द्वारा 52 प्रकार के आपरेशन करने की मंजूरी देने के विरोध में आइएमए ने सुवह छह से शाम छह वजे तक वहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने केवल गंभीर मरीजों को ही देखा और उन्हें परामर्श दिया। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संशोधन किया है। इसमें उन्होंने वताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी 52 प्रकार के आपरेशन कर सकेंगे। इसका एलोपैथिक डाक्टर व आइएमए विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि दोनों की शिक्षा में काफी अंतर है। अगर आयुर्वेदिक डाक्टर द्वारा किए गए आपरेशन के वाद मरीज की स्थिति विगड़ी तो उसे सुधारने का प्रतिशत काफी कम रहेगा। -नप्र

लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने जारी किए आदेश

प्रदेश के दो लाख 37 हजार अध्यापकों को छठवें वेतनमान की तीसरी किस्त मिलेगी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान करने संबंधी आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्त जयश्री कियावत ने अध्यापक संवर्ग को एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश में लिखा है कि अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान के एरियर के लिए एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किए जाने के निर्देश दिए गए थे। फिर शासन की ओर से 29 जुलाई 2020 को रोका गया था। फिर से शासन द्वारा 9 दिसंबर को छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश से प्रदेश के दो लाख 37 हजार अध्यापकों को फायदा मिलेगा। एक-एक अध्यापक को करीब 25 से 30 हजार रुपये मिलेगा।

15 माह का सातवें वेतनमान का एरियर बकाया

नए कैडर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में अध्यापक संवर्ग की जुलाई 2018 में नियुक्ति की गई थी। शासन के आदेश पर नए कैडर के तहत अध्यापकों को जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सितंबर 2019 तक का भुगतान अब तक नहीं हुआ। अध्यापकों को सितंबर पैड अक्टूबर 2019 से सातवें वेतनमान के तहत एरियर का नकद भुगतान किया गया।

शासकीय अध्यापक संगठन की मांग पर शिक्षा विभाग ने छठवें वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन को सातवें वेतनमान का 15 माह का एरियर भुगतान करने के आदेश भी जारी करना चाहिए।

उपेंद्र कौशल, प्रदेश संयोजक, शासकीय अध्यापक संगठन

शिक्षकों को छठवें वेतनमान के एरियर की मिलेगी तीसरी किश्त

आयुक्त लोक शिक्षण ने जारी किए आदेश

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त के भुगतान करने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने आदेश जारी कर अध्यापक संवर्ग को एरियर की तीसरी किश्त भुगतान करने के आदेश जारी किए है। इसके तहत अध्यापक संवर्ग के छठवां वेतनमान की एरियर के लिए 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किश्तों में 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किए जाने के निदेश दिए गए थे। इसके बाद शासन की ओर से 29 जुलाई 2020 को आदेश पर रोक लगा दी गई थी। फिर से शासन ने 9 दिसंबर को छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किए जाने के आदेश दिए। इसे लेकर आयुक्त लोक शिक्षण ने भी भुगतान के आदेश जारी कर दिए है।

गौरतलब है कि अध्यापक संगठन 15 माह का बकाया एरियर्स और छठवें वेतनमान की तृतीय किश्त का भुगतान करने की मांग कर रहे थे। शासकीय अध्यापक संगठन के प्रदेश संयोजक उपेंद्र कौशल ने कहा कि शासकीय अध्यापक संगठन की लगातार ज्ञापन द्वारा शिक्षा विभाग से छठवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं।

जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के पहले दिन 11 हजार 223 ने दी परीक्षा, 12 हजार 37 रहे अनुपस्थित

खराब मौसम व ट्रांसपोर्ट व्यवस्था न होने के डर से पहली शिफ्ट पर ही सेंटर पहुंच गए दूसरी पाली के परीक्षार्थी

हरिभूमि न्यूज >> भोपाल

प्रदेश में 282 पदों के लिए जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा दो पालों में शुक्रवार से शुरू हुई। पहले दिन 11 हजार 223 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 12 हजार 37 अनुपस्थित रहे। चूंकि परीक्षा केंद्र शहर से बाहर बनाए गए थे, इसलिए परीक्षार्थी समय से पहले ही इन केंद्रों पर पहुंच गए। खराब मौसम और ट्रांसपोर्ट न मिलने के डर से दूसरे शहरों से राजधानी आए दूसरी पाली के परीक्षार्थी पहली पाली के समय पर ही केंद्रों पर पहुंच गए। सुबह 8 बजे ग्वालियर, होशंगाबाद, हरदा, गुना सहित कई जिलों के परीक्षार्थी केंद्र के सामने बैठे मिले, जबकि उनकी रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1 बजे तक थी। सुबह की पाली में 8 बजे और दोपहर की पाली में दोपहर 1 बजे के बाद केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके कारण कुछ आवेदक परीक्षा नहीं दे पाए। सुबह की पाली 9 से 11 बजे तक में उपस्थिति 48.28 प्रतिशत रही। इस पाली में 5274 ने परीक्षा दी, जबकि 6131 अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थिति 50.18 प्रतिशत रही। 5949 ने परीक्षा दी, जबकि 5906 अनुपस्थित रहे।

खास बातें

- सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे के बाद नहीं मिली केंद्र में प्रवेश की अनुमति
- सुबह आठ बजे होशंगाबाद, ग्वालियर, हरदा, गुना सहित अन्य राज्यों से आए परीक्षार्थी बाहर बैठे मिले

आईईएस कॉलेज परिसर में बाहर से आए परीक्षार्थी अपने समय का इंतजार करते हुए

भोपाल में रही 45.23 फीसदी उपस्थिति

राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पहले दिन 45.23 फीसदी उपस्थिति रही। पहली पाली में 2655 में से 1162 ने परीक्षा दी। वहीं 1493 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली में 2655 में से 1240 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1415 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 43.77 और दूसरी पाली में 46.70 प्रतिशत उपस्थिति रही।

24 दिसंबर तक चलेगी परीक्षा

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) द्वारा आयोजित जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 24 दिसंबर तक चलेगी, इस दौरान सिर्फ 17 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा में 3 लाख 6 हजार परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना जरूरी है। परीक्षा के लिए ब्लैक पॉइंट पेन लाना आवश्यक है।

केंद्रों के सभी कक्षों को किया गया सेनिटाइज

परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों को सेनिटाइज किया गया, जिस जगह पर परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, उसे पूरी तरह सेनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान मॉनिटर, की-बोर्ड, माउस, डेस्क फिक्सर, डेस्क और कुर्सी समेत दरवाजे के हैंडल, सीढ़ी की रेलिंग, लिफ्ट के बटन आदि को भी सेनिटाइज किया जा रहा है। प्रत्येक परीक्षार्थी को अपना हैंड सेनिटाइजर और पानी की बोतल अंदर ले जाने दिया गया।

टफ था पेपर

एसटी-डीजी करंट अफेयर्स से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे गए। मैथ्स के प्रश्न [illegible] थे पर [illegible] गया। ओवरऑल पेपर थोड़ा टफ ही था। मेरिट हाई जाएगी।

- रोहित सिंह, [illegible]।

समय पर आया

2017 में आवेदन कर दिया था, विदिशा सेंटर मिला था। ट्रेन 7 घंटे लेट हो जाने से पेपर ही छूट गया था। इस बार समय पर आ गया।

- सैयद इरफान अहमद, ग्वालियर

फ्रांस में पेश विवादित विधेयक

सिर्फ धर्मस्थल होंगी मस्जिदें, पढ़ाई स्कूलों में

पेरिस | एजेंसी

फ्रांस की सरकार बुधवार को एक नया विधेयक लेकर आई है जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग स्विमिंग पूल्स को खत्म कर दिया जाएगा और तीन साल की उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। कहा जा रहा है कि देश में ऐसा कानून लाकर 'इस्लामिक कट्टरवाद' से लड़ने की तैयारी की जा रही है जिसे लेकर देश के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों मुस्लिम आबादी और देशों के निशाने पर रहे हैं।

होम-स्कूलिंग की इजाजत नही

प्रस्तावित कानून के जरिए घर पर पढ़ाई करने , मस्जिदों और ऐसे संगठनों पर नियम लागू किए गए हैं जो फ्रांस के मूल्यों के खिलाफ किसी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले हों। इसके तहत तीन साल की उम्र के बाद बच्चों की होम-स्कूलिंग की इजाजत सिर्फ खास परिस्थितियों में दी जाएगी। इसके तहत अवैध स्कूलों पर नकेल कसने की बात की जा रही है जहां किसी खास अजेंडे के तहत पढ़ाई कराई जाती है।

हैं कई नियम

इसके अलावा मस्जिदों को पूजास्थल के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा ताकि उनको बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। किसी जज को आतंकवाद, भेदभाव, नफरत या हिंसा के दोषी को मस्जिद जाने से रोकने का भी अधिकार होगा। 10 हजार यूरो से ज्यादा विदेशी फंडिंग होने पर उसे डिक्लेयर भी करना होगा। वहीं, एक से ज्यादा शादी करने वालों को रेजिडेंस कार्ड भी नहीं दिए जाएंगे।

कानूनों में बदलाव जरूरी

वहीं देश के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने इस बात पर जोर दिया है कि विधेयक मुस्लिम या किसी और धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया है कि विधेयक में देश के 1905 के कानून में बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें चर्च को सरकार से अलग करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल्यों, परंपराओं और खतरों में बदलाव के कारण धर्मनिरपेक्षता कानून और 1901 के उस कानून में बदलाव की जरूरत है जिसके नियम असोसिएशन पर लागू होते हैं।

नई शिक्षा नीति भारत को 'पुनः विश्व गुरु' बनाने की दिशा में प्रभावी कदम : निशंक

ब्यूरो नई दिल्ली | केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर छात्र तथा हर कोने तक समान और समावेशी रूप से शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आई है। उन्होंने यह विचार सीबीएसई सहोदय स्कूल परिसरों के 26वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

चुनिंदा कॉलेजों को छोड़कर जबलपुर मेडिकल से सुपरस्पेशलिस्ट बनने की चाह

न्यूरो सर्जरी वैल्लूर और केईएम जैसे संस्थानों से ऊपर जबलपुर न्यूरो सर्जरी विभाग को महत्व दे रहे नए सुपरस्पेशलिस्ट, डॉ. यादव ने कहा- यह शहर के लिए बड़ी बात

भास्कर समाचार सेवा | जबलपुर

देश के ऐसे चिकित्सक जिनको न्यूरो सर्जरी में एमसीएच करने का मौका मिल रहा है वे देश के चुनिंदा मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट की बजाय जबलपुर मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग से सुपरस्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं। मौलिक ट्रेनिंग, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में महारत और बेहतर फैकल्टी के मद्देनजर डॉक्टर न्यूरो का महारथी संस्कारधानी से बनने की चाहत रखते हैं। ताजा प्रोविजनली सुपरस्पेशलिस्ट एलॉटमेंट रिजल्ट में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज न्यूरो सर्जरी विभाग सीएमसी वैल्लूर, केईएम मुंबई, केजीएमसी लखनऊ, एसएमएस जयपुर, आरएमएल लखनऊ, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जेजे हॉस्पिटल मुंबई, बीएचयू आदि इंस्टीट्यूट और कॉलेजों से ऊपर है। विभाग के मुखिया और सीनियर न्यूरो सर्जन डॉ वाय. आर. यादव कहते हैं कि यह शहर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है।

डॉ. यादव के अनुसार देश के बड़े, चुनिंदा और कई लिहाज से उम्दा माने जाने वाले संस्थानों की बजाय यहाँ न्यूरो सर्जरी का विशेषज्ञ बनने आना, कहीं न कहीं यह बताता है कि यहाँ भी सर्जरी का काम इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है। जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी न्यूरो सर्जन को यहाँ सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जाती है उसका लोहा अब देश में माना जा रहा है। कोशिश आगे यही है कि शहर का नाम रोशन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जटिल बीमारी से ग्रसित होने पर सहज इलाज यहीं पर मिल सके।

इंटरव्यू में एपीएसयू के किसी भी प्रोफेसर को नहीं बुलाया

कौन बनेगा विवि कुलपति सोमवार तक होगा फैसला

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा। इसका फैसला संभवत सोमवार या मंगलवार को हो जाएगा। राजभवन बीते दो दिनों से कुलपति के दावेदारों और सर्च कमेटी का इंटेरेक्शन और साक्षात्कार चल रहा था जो सम्पन्न हो चुका है। बता दें कि इस बार कुलपति के चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसरों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति बाहरी होंगे।

स्टार समाचार | रीवा

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर एनपी पाठक को कुलपति का प्रभार दिया गया और उसके बाद से ही नए कुलपति की नियुक्ति करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। इस बार के चयन प्रक्रिया में एक ही बदलाव रहा कि कुलपति सर्च कमेटी के एक सदस्य कार्य परिषद से नहीं चुने गए बल्कि राज्य सरकार की ओर से सदस्य मनोनीत किए गए। बाकी राजभवन और यूजीसी की ओर से एक-एक सदस्य मनोनीत किए गए थे। तीनों सदस्यों ने आपस में बैठकें की और अंतिम दिन आवेदकों का नाम फाइनल किया। बताया गया है कि वह तीन आवेदक कौन है यह जानकारी गोपनीय है। सर्च कमेटी जिसे भी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति को चुने अंतिम फैसला मध्य प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति का होगा। जिसे राज्यपाल चाहेंगे उसे कुलपति बना देंगे।

पिछली बार विवि से गए थे तीन प्रोफेसर

ताज्जुब की बात यह है कि इस कुलपति की चयन प्रक्रिया में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसर को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि पिछली बार विश्वविद्यालय से तीन प्रोफेसर को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया था। जिनमें से वर्तमान प्रभारी कुलपति प्रो. एनपी पाठक, प्रो. शोभा तिवारी और प्रो. सुनील तिवारी का नाम शामिल था। मगर इस बार राजभवन की ओर किसी को बुलावा नहीं आया। ऐसे में विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों को इस बात का अफसोस है कि जो कुलपति बनने की पात्रता रखते हैं। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के किसी भी दावेदार को इंटरव्यू में न बुलाने की वजह यह है कि आवेदन भरते समय ही प्रोफेसर एक-दूसरे की टांग खिचाई करने में लग गए थे। कोई किसी पर झूठे आरोप लगा रहा था तो पुराने प्रकरणों को भोपाल तक पहुंचाया जा रहा था। जिसके कारण कई प्रोफेसर के आवेदन ही नहीं स्वीकार नहीं किए गए तो कइयों को एनओसी भी नहीं मिली।

डॉ. भरत मिश्रा के व्हीसी बनने की संभावनायें ज्यादा

चित्रकूट विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर डॉ. भरत मिश्रा के विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनने की संभावनायें ज्यादा बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो अंतिम तीन आवेदकों में से एक नाम डॉ. मिश्रा का है। यह भी पता चला है कि डॉ. मिश्रा को व्हीसी बनाये जाने के लिए उच्च स्तर से जोर दिया जा रहा है। हलांकि डॉ. भरत मिश्रा के पास 27 साल के रिसर्च और अध्यापन का अनुभव है। इसके अलावा उनके द्वारा 85 से अधिक रिसर्च पेपर, तीन किताबें पब्लिस की गई है। उन्होंने 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कान्फ्रेंस, वर्कशॉप और ट्रेनिंग में हिस्सा ले चुके है। बताया गया है कि डॉ. मिश्रा के गाइडेंस में तैयार की 20 पीएचडी थिसिस को एवार्ड मिल चुका है। साल 2011 में वह बेस्ट साइंस रिसर्च से सम्मानित किए गए थे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी का स्वागत

स्टार समाचार | सीधी

लम्बे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जा रहा था। इस धरना प्रदर्शन में भाकपा राज्य परिषद सदस्य काम. आनंद पाण्डेय के नेतृत्व में कई बार समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या को लेकर लगातार संघर्ष के बदौलत अब सरकार के कान खड़े हुए एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने सहित मोबाइल के लिए 10-10 हजार रुपए अलग से खाते में डालने का फरमान जारी किया है।

बताया गया है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2018 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 सौ रुपए बढ़ाकर 6500 रुपए मानदेय करने की घोषणा की। राज्य शासन ने 27 जून 2019 को आदेश दिया कि 15 सौ रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घटाकर 3 हजार 500 रुपये कर दिया। पहले 5 हजार रुपया राज्य शासन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता था। इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 11 हजार 500 रुपये मिलना चाहिए था। जिसके कारण पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपया मिलता था और आज भी 10 हजार रुपया मिलता है। एटक मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश के सचिव एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता कामरेड अरविंद श्रीवास्तव ने राज्य सरकार के इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विरोधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 14501/2019 प्रकरण के माध्यम से 27 से 2019 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 सौ रुपया प्रति माह के हिसाब से एरियर्स का भुगतान करते हुए नियमित रूप से 11 हजार 5 सौ रुपए प्रति माह देने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट दायर किया है 10 दिसंबर 2020 को इसकी सुनवाई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को हिदायत दिया है कि इस संबंध में राज्य शासन अपना जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा जो बातें एटक यूनियन ने अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव के जरिए कही है उसको मानते हुए एक तरफा फैसला किया जायेगा। इस के बाद कुछ और यूनियनों ने हाल फिलहाल इस संबंध में उच्च न्यायालय में एटक का देखा देखी करके अपील किया है हम इसका स्वागत करते हैं और एटक को विश्वास है की 27 जून 2019 से हर हाल में पंद्रह सौ रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कटा हुआ पैसा मिलेगा। इस संबंध में काम. आनंद पाण्डेय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित होगी कोई रोक नहीं सकता है। साथ उन्होंने आशा जाहिर की है कि आगे भी ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ शासन-प्रशासन उनका मनोबल बढ़ाता रहे।

15 अधिकारियों का कटेगा एक दिन का वेतन, चार को नोटिस

नगर संवाददाता | जबलपुर

जनता से जुड़े मामलों में अब लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की शुरूआत हो गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट मंगाई और तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये। सूची में ऐसे 15 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये, जिन्होंने सीएम हैल्पलाइन से जुड़ी 10 से ज्यादा शिकायतों को आगे बिना निराकरण किये फारवर्ड कर दिया था। इसी तरह बैठक में कई अधिकारी न तो पहुँचे और न ही अपने अधीनस्थ को भेजा ऐसे विभागों को भी नोटिस जारी करने कहा गया। समाधान एक दिवस और सीएम हैल्पलाइन को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक बुलाई गई और बैठक में ऐसे अधिकारियों को बुलाया गया था, जिनकी लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही निचले स्तर पर ही शिकायतों का निपटारा करें अन्यथा उच्च अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश बाथम, बीपी द्विवेदी व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इनको मिले नोटिस | कलेक्टर ने मेडिकल के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शालिगराम मरावी का वेतन काटने और नोटिस जारी करने कहा। इसी तरह प्राचार्य आयुर्वेद कॉलेज एलएल अहिरवाल को नोटिस व आरटीओ संतोष पॉल को बैठक में उपस्थित न होने एवं लीड बैंक के मैनेजर के उपस्थित न होने पर नोटिस जारी करने कहा। इसी तरह वन विभाग से भी कोई नहीं पहुँचा जिस पर डीएफओ का पत्र लिखने की बात कही।

इनका काटा जाएगा वेतन | बैठक में निर्देश दिये गये कि इनका एक दिन का वेतन काटा जाये। जिसमें उदयराज सिंह सीएमओ जनपद पंचायत पनागर, दिलीप दुबे कार्यालय अधीक्षक नवि, अंजू ठाकुर नोडल अधिकारी नवि, सुधीर दुबे सहायक आपूर्ति नियंत्रक, मितानी मेहरा जेएसओ, सिद्धार्थ राय जेएसओ, अंजलि सेलट बीईओ, खनिज अधिकारी पीके तिवारी, दीपा बारेवार खनिज निरीक्षक, नीरज कुचया कार्यपालन यंत्री, सुमित अबिद्रा कनिष्ट अभियंता, बीपी रैकवार कार्यपालन अभियंता, एसएस मनकोटिया कनिष्ठ अभियंता, दीपेश मिश्रा डिप्टी रजिस्ट्रार एवं मोहित भारती सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग आदि शामिल हैं।पी-2

पालक महासंघ ने लोक शिक्षण आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर तीन मांगें उठाईं, कहा-

स्कूल खोलना ठीक नहीं, 11वीं तक जनरल प्रमोशन दें

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा अगले हफ्ते से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद पालक महासंघ विरोध में उतर आया है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूल खोले गए तो बच्चों में संक्रमण का खतरा रहेगा।

महासंघ ने शुक्रवार को लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत से भी मुलाकात कर अपनी चिंता से अवगत कराया। तीन सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। महासंघ का कहना है कि इस साल कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं। दो माह स्कूल लगाकर विद्यार्थियों को कौन सा फायदा हो जाएगा। सरकार को इस समय सिर्फ 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने और परीक्षा लेने के आदेश जारी करना चाहिए। 12वीं कक्षा के आधार पर ही मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य कॉलेजों में एडमिशन मिलता है।

पालक महासंघ की ये हैं मांगे

1. विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 11वीं तक स्कूल न खोले जाएं।
2. प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस की मनमानी वसूली पर रोक लगाई जाए।
3. डेढ़ माह के लिए सत्र शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। 11वीं तक जनरल प्रमोशन दिया जाए।

स्कूल जाने में डर लग रहा है

यदि परीक्षाएं होना है, तो पढ़ाई जरूरी है। यह पढ़ाई स्कूल में ही अच्छे से हो सकती है। लेकिन, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उससे स्कूल जाने में डर लग रहा है। अब परीक्षा में दो महीने बचे हैं, कुछ रिवीजन तो हो ही जाएगा।

-सुरेश गंगराड़े, स्टूडेंट 12वीं

स्कूल खोलना अभी ठीक नहीं

यह सही है कि जनरल प्रमोशन ठीक नहीं है। बीच में हमारे टेस्ट व छमाही परीक्षाएं हुई हैं, उसके आधार पर इंटरनल असेसमेंट और ऑनलाइन एग्जाम के नंबर मिलाकर वार्षिक एग्जाम कराए जाएं। स्कूल खोलना अभी ठीक नहीं है।

-मनीष द्विवेदी, स्टूडेंट 10वीं

जनरल प्रमोशन ठीक नहीं

जनरल प्रमोशन बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमने 5वीं तक स्कूल बंद करने को कहा है। बाकी बच्चों की मार्च की जगह मई में परीक्षा भले हो, इसके लिए सेशन शुरू करने की मांग हमने की है।

-बाबू थॉमस, सचिव, एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल, मप्र

...तो जिम्मेदार कौन होगा

बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर आठवीं तक स्कूल बंद रखे जाएं। साल भर पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए 1 से 12वीं तक विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। स्कूल खुलने पर बच्चा संक्रमित होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा। -कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष, मप्र पालक महासंघ

आरजीपीवी: सभी सेमेस्टर के थ्यौरी एग्जाम जनवरी में होंगे

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के सभी सेमेस्टर के एग्जाम जनवरी में होंगे। दिसंबर अंत में सभी सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ सातवें सेमेस्टर के थ्यौरी एग्जाम भी शुरू होंगे। टाइम टेबल शीघ्र ही आरजीपीवी के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रो. एके सिंह ने बताया कि 7वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन और अन्य सेमेस्टर की ओपन बुक सिस्टम से कराने का प्रस्ताव बनाया गया है। ईसी की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

परीक्षा

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अब 31 दिसंबर तक

भोपाल। एमपी टॉस के पीएमएस माड्यूल वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के तहत पोस्ट मैट्रिक

योजना

छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिए अभी तक शत-प्रतिशत छात्रों ने आवेदन नहीं किए हैं। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ विभागों ने पूरा डाटा अपलोड नहीं किया। इसके चलते वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर एवं वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है।

परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों की एग्जाम जनवरी में

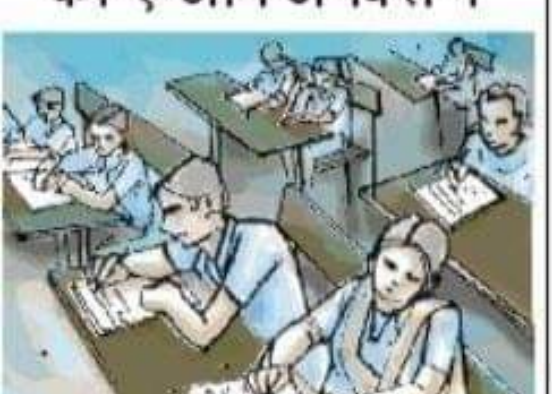

इंदौर। ओपन वुक परीक्षा से वंचित हुए विद्यार्थियों को साल बचाने का मौका मिलने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पेशल एग्जाम करवाने को लेकर प्रदेशभर के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सप्लीमेंट्री और एटीकेटी वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। विभाग ने परीक्षा अगले महीने कराने की बात कही है।

कोरोना के कारण विभाग ने यूजी-पीजी कोर्स के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की ओपन वुक पद्धति से परीक्षा करवाई। अगस्त-सितंबर में हुई परीक्षा में सैकड़ों विद्यार्थी शामिल नहीं हो सके, क्योंकि अधिकांश कंटेनमेंट एरिया में रहते थे। जबकि कुछ विद्यार्थी संक्रमण का शिकार हुए थे। वैसे विभाग ने पहले ही निर्देश दिए थे कि जो विद्यार्थी अभी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते उनके पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) को पत्र लिखते हुए पिछली परीक्षा के पेपर पोर्टल से हटाने के लिए कहा है ताकि अगली परीक्षाओं के पेपर अपलोड किए जा सकें। अतिरिक्त शिक्षा संचालक प्रो.सुरेश सिलावट ने बताया जनवरी-फरवरी के बीच परीक्षा करवाई जाएगी।

संचालकों ने लोक शिक्षण आयुक्त को दिया ज्ञापन

14 दिसंबर से पहले नहीं खुले निजी स्कूल तो CM हाउस पर करेंगे प्रदर्शन

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

कोरोना संकट के कारण बंद चल रहे निजी स्कूलों के संचालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बिजली, पानी, वाहनों की किश्त, टैक्स से लेकर बैंक के कर्ज अदा न कर पाने से स्कूल संचालक कर्ज में डूब गए हैं। ऐसे में शहर के निजी स्कूलों के संचालकों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल दो दिन में खोलने का निर्णय लेने को कहा है। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत को दिए ज्ञापन में निजी स्कूलों के संचालकों ने निर्णय न होने पर 14 दिसंबर को सीएम हाउस पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। स्कूल संचालकों का दावा है कि सीबीएसई और एमपीबोर्ड के स्कूलों को खोले जाने को लेकर आज-कल में फैसला हो सकता है। सीपीआई के अनुसार उनकी मांगों का ड्राफ्ट बनाकर शासन को भेज दिया है। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल संचालक भी पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास शुरू करने के पक्ष में नहीं है।

ऑनलाइन क्लास भी करेंगे बंद

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर 14 दिसंबर तक स्कूल नहीं खोले गए, तो आंदोलन शुरू होगा। 14 दिसंबर को सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास घेरा जाएगा। इसके बाद ऑन लाइन क्लास बंद कर दी जाएंगी।

खाली पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की मांग

भोपाल। मानव अधिकार दिवस पर गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों ने

सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की। परीक्षार्थियों का नेतृत्व कर रहे रंजीत गौर ने बताया कि हमने प्रदेश के शासकीय स्कूलों में समस्त रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। अभ्यर्थियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीएम एवं राज्यपाल से गुहार लगाई है।

निरीक्षण होने पर निजी विवि के खिलाफ UGC लेगा एक्शन

100% फीस के बावजूद प्रोफेसरों को मिल रही 40-60% सैलरी

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन राज्य के निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ स्टाफ की सैलरी की कटौती अभी भी जारी है। सैलरी की कटौती होने के कारण सभी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। इससे प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालयों को अपना इस्तीफा भेजना शुरू कर दिए हैं।

सूबे में 37 निजी विवि संचालित हो रहे हैं, जो सभी प्रोफेशनल कोर्स एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि, बीएड, आईटीआई और उच्च शिक्षा के कोर्स में प्रवेश देकर सभी विद्यार्थियों ट्यूशन फीस के साथ अन्य प्रकार के शुल्क के साथ फीस शत प्रतिशत तक जमा करा ली हैं, लेकिन निजी विवि प्रोफेसर सहित अन्य स्टाफ को शत प्रतिशत सैलरी आवंटित नहीं कर रहे हैं। वे उनकी 40 से 60 फीसदी तक सैलरी में कटौती कर जारी कर रहे हैं। इससे उन्हें काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इससे उनके बैंक एकाउंट में साठ से चालीस फीसदी सैलरी ही जमा हो रही है।

मान्यता-संबद्धता पर भी आ सकता है संकट

इस्तीफे पहुंचने से निजी विवि का शैक्षणिक स्टाफ एआईसीटीई, एमसीआई, बीसीआई और यूजीसी के मापदंडों से दूर हटने लगे हैं। एआईसीटीई ने आदेश तक जारी कर दिया है कि उनके कोर्स में मापदंड के मुताबिक फैकल्टी नहीं मिलने पर वे विवि का निजी विवि का निरीक्षण करेंगे, जिसमें गड़बड़ी होने पर उनकी मान्यता खत्म करने के लिए यूजीसी और राज्य सरकार से अनुशंसा तक की जाएगी। हालांकि इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर कालेज के रिकार्ड पर दर्ज बने हुए हैं। निरीक्षण के दौरान निजी विवि की पोल खुलना तय है।

क्या कहतें हैं प्रोफेसर...

प्रोफेसरों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान पूरा तक पूरा वेतन देने के लिए कहा था। अब तो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थियों की पूरी फीस लेने के बाद ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं, जिसमें वे पूरा समय दे रहे हैं। इसके बाद भी उनकी सैलरी में काफी कटौती हो रही है। इसके संबंध में चौतरफा शिकायतें भी की जाएगी। वेतन में कटौती होने के बाद प्रोफेसर एक-एक अपने विवि मनैजमेंट को इस्तीफा भेजना शुरू कर दिए हैं।

प्रदेश में संचालित निजी विवि

भोपाल: सर्वपल्ली राधाकृष्णनन विवि, मध्यांचल विवि, भाभा विवि, एलएनसीटी विवि, जागरण लेकसिटी विवि, रबींद्रनाथ टैगोर विवि।

इंदौर: श्री वैष्णवी विद्यापीठ विवि, मेडिकैप विवि, रेनासेंस विवि, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विवि, मावलांवल विवि, सिम्बिओसिस, संज विवि, ओरिएंटल विवि।

सीहोर: मानसरोवर विवि, एचआईटी विवि, श्री सत्य साई विवि।

ग्वालियर: आईटीएम विवि, अमिटी विवि ग्वालियर।

गुना: जेपी विवि, सागर: एसएचएम विवि, सतना: एकेएस विवि, सिरोंज: टेक्नो ग्लोबल विवि, शिवपुरी: पीके विवि मंदसौर: मंदसौर विवि, छिंदवाडा: एचजी रायसोनी विवि, उज्जैन: अवंतिका विवि, बालाघाट: सरदार पटेल विवि, खंडवा: डॉ. सीव्ही रमन विवि, छतरपुर: श्री कृष्णा विवि।

मापदंड के मुताबिक फैकल्टी नहीं मिलने पर निजी विवि के कोर्स का निरीक्षण कराया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर यूजीसी और राज्य सरकार से एक्शन लेने अनुशंसा की जाएगी।

अनिल सहस्त्रबुद्धे
अध्यक्ष, एआईसीटीई

Published in 12 Dec-2020 print edition of Raj Express

तार टूट कर गिरा, शिक्षिका स्कूटी सहित जिंदा जली

बांसवाड़ा में हुआ दिल दहलाने वाला हादसा

बांसवाड़ा, (एजेंसी)। मप्र से सटे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के ग्राम नौगामा में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश में दिल दहलाने वाला दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में स्कूटी पर स्कूल जा रही शिक्षिका नीलम पाटीदार (25)की जिंदा जलने से मौत हो गई। वह स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में बिजली तार उस पर आ गिरा। इससे करंट फैला और स्कूटी में आग लग गई।

इससे स्कूटी सहित शिक्षिका जल गई। बिजली तार टूटकर स्कूटी पर लिपट गया और धमाके की आवाज के साथ करंट फैलने से आग लग गई। आग ने स्कूटी के साथ गिरी नीलम को भी चपेट में ले लिया। वह जलती हुई तड़पती रही, लेकिन सड़क पर पानी होने व करंट फैलने से लोग उसे बचाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए।

शहर में 30 हजार बच्चों को मिलेगा दाल-तेल, 1200 रहेंगे इससे वंचित

विभाग की मैपिंग में नाम नहीं आने से 1,000 से अधिक बच्चों को लाभ नहीं

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्याह्न भोजन के रूप में दी जा रही है यह सामग्री

भोपाल ■ राज न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल में करीब 1000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में तो पढ़ रहे लेकिन आज तक उनका समग्र आईडी नहीं बनने के कारण मैपिंग में नाम गायब है। ऐसे बच्चे राजधानी में सरकार द्वारा वितरित की जा रही खाद्य सामग्री से वंचित किए जा रहे हैं।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश पर प्रदेश के समस्त सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग दाल और तेल का वितरण करने जा रहा है। यह वे बच्चे हैं जिनको स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मध्याह्न भोजन कराया जाता था। मौजूदा वर्ष में कोरोना का जबरदस्त संकट चल रहा है। इस कारण प्रदेश में कोई भी स्कूल नहीं खुला है, जबकि नियम के अनुसार जुलाई माह से ही बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलना जरूरी था। कारण भी है कि इसका पहले ही बजट शासन से जारी हो चुका था। महामारी के बढ़ते खतरे को लेकर जब स्कूल नहीं खुले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब बच्चों को किसी न किसी रूप में भोजन का लाभ देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था। पहले यह नीति बनी थी कि अगर बच्चों को भोजन नहीं कराया जाता है तो फिर उस अनुदान का पैसा मिले या फिर राशि उनके खाते में डाल दी जाए।

अधिकारियों ने बच्चों के खातों में राशि डालने की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन अधिकांश बच्चों का खाता बंद होने के कारण यह काम शत प्रतिशत सफल नहीं हो पाया था। तब रणनीति बनी थी कि क्यों ना बच्चों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाए। कुछ महीने पहले भी कंट्रोल के माध्यम से बच्चों को स्कूलों में ही राशन का वितरण हुआ था। अब बच्चों को दाल और तेल का वितरण करवाया जा रहा है।

बच्चों को मिलेगा दाल और तेल मुहैया कराया जाएगा

राजधानी के फंदा नया और पुराना बीआरसीसी क्षेत्र में 30,000 से अधिक बच्चों को दाल और तेल मुहैया कराया जाएगा। फंदा नया शहर बीआरसीसी नरेंद्र सिंह दुबे ने बताया कि उनके क्षेत्र की समस्त मिडिल और प्राइमरी शालाओं के 20,000 बच्चों को दाल और तेल मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्राइमरी में आधा किलो तेल एवं 2 किलो तुअर की दाल प्रत्येक बच्चे के नाम से वितरित की जाएगी। जबकि मिडिल में साढ़े 700 ग्राम तेल और 3 किलो तुअर की दाल बच्चों को वितरित होगी। नरेंद्र सिंह दुबे का कहना है कि करीब 500 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह ऐसे बच्चे हैं जिनका मैपिंग में नाम नहीं हो पाया है। दुबे का कहना है कि इन बच्चों की समग्र आईडी ना बनने के कारण उनका नाम मैपिंग में नहीं आ पाया है। इधर फंदा पुराना शहर में 14,000 बच्चों की बाकायदा मैपिंग में दर्ज की गई है। इन सभी बच्चों को दाल और तेल मिलेगा। लगभग 680 बच्चे हैं जिनका नाम मैपिंग में नहीं आने के कारण उन्हें राशन वितरण की सूची में नहीं जोड़ा गया है।

अन्नदाता की समृद्धि के लिए समर्पित सरकार
नए भारत का निर्माण, सबसे पहले किसान

भारत को अपने अन्नदाताओं पर बहुत गर्व है। वे देश का पेट भरने के लिए दिन-रात काम करते हैं। हम अपने किसानों को सशक्त करने के लिए सुधारों और दूसरे अन्य उपायों के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में जुटे हैं।

- नरेन्द्र मोदी

किसानों के हित में संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कानून

इन कानूनों से क्या नहीं होगा?

MSP सिस्टम खत्म नहीं होगा।

APMC मंडियां बंद नहीं होंगी।

किसानों की जमीन कोई भी नहीं छीन सकता।

किसानों का एग्रीमेंट द्वारा बंधन नहीं होगा।

इन कानूनों से क्या होगा?

बंधनमुक्त राष्ट्रीय बाजार से किसानों की आय बढ़ेगी।

MSP सिस्टम जारी रहेगा, किसान अधिक दाम के लिए खरीदार से मोल-भाव कर सकते हैं।

किसान APMC मंडियों में और बाहर भी, जहां दाम अधिक मिले, फसल बेच सकते हैं।

फसल के मूल्यों के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी।

उच्च मूल्य की नई किस्म की फसलों के लिए बाजार उपलब्ध होगा।

फसल बुआई से पहले और कटाई के बाद, दोनों स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप कमाई के बेहतर विकल्प।

ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि-व्यवसाय में अधिक अवसर।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश और इनोवेशन, ग्रामीण युवाओं के लिए अधिक रोजगार।

झूठ पर विश्वास न करें, सच्चाई को जानें

झूठ	सच
MSP की व्यवस्था खत्म हो रही है।	MSP सिस्टम जारी है, जारी रहेगा।
APMC मंडियां बंद की जा रही हैं।	APMC मंडियां कायम रहेंगी। APMC मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं।
किसानों की जमीन खतरे में है।	एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा।
किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन हथिया सकते हैं।	परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है।	फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का सटीक मूल्य दर्ज किया जाएगा।
किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा।	किसानों का भुगतान तय समयसीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा।
किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं।	किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं।
पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है।	कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक हैं।
इन कानूनों को लेकर कोई सलाह-मशविरा या चर्चा नहीं की गई है।	दो दशकों तक विचार-विमर्श हुआ है। साल 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल APMC एक्ट; 2007 के APMC Rules; 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति; 2017 का मॉडल APLM एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी।

davp 01101/13/0020/2021

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

आज देश किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और इसे पाने के लिए देश की सामूहिक शक्ति लगातार प्रयासरत है।

अप्रैल में रोकी गई तीसरी किस्त के आदेश जारी,ढाई लाख अध्यापकों को होगा भुगतान

कोरोना के कारण रोक दी थी छठवें वेतनमान की तीसरी किस्त

भोपाल (आरएनएन)। अप्रैल माह में शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों की रोकी गई छठे वेतनमान की तीसरी किस्त का अब भुगतान होगा। लोक शिक्षण संचालनालय कि आयुक्त जयश्री कियावत ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से प्रदेश भर के करीब ढाई लाख अध्यापक लाभान्वित होंगे।

कोरोना के आकस्मिक संकट को लेकर अप्रैल माह में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ-साथ अध्यापकों के एरियर की तीसरी किस्त रोक दी गई थी। शिवराज से पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 25 फीसदी राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए गए थे। इधर अध्यापकों को छठवां वेतनमान में तीसरी किस्त का लाभ

परेशान जिला शिक्षा अधिकारियों ने मांगा था संचालनालय से मार्गदर्शन

मिलना था लेकिन इसके आदेश जारी नहीं हुए थे। तब से अध्यापक लगातार प्रदेश भर में इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को फोनबाजी कर रहे थे। जब विशेष बाद में जिला शिक्षा अधिकारियों ने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा था। इस मामले पर विचार करते हुए शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आहरण संवितरण अधिकारी सुविधा से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अध्यापकों को छठे वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान किया जाए। इस भुगतान से संबंधित अवधि भी निर्धारित की गई है। यह राशि सीधे अध्यापकों के वेतन में जोड़ी जाएगी।

प्रदेश के अध्यापकों ने ली राहत की सांस

इसके बाद आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के अध्यापकों ने राहत की सांस ली है। राज्यस्तरीय अध्यापक संगठन प्रदेश अध्यक्ष … का कहना है कि तीसरी किस्त के लिए बड़ा संघर्ष किया है। लगातार शासन द्वारा शिक्षा विभाग से छठे वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त के भुगतान की मांग पर आयुक्त ने किस्त भुगतान पर लगी रोक हटाते हुए तृतीय किस्त भुगतान करने के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि इस भुगतान से संबंधित आदेश जारी होने के बाद प्रदेशभर के अध्यापकों ने संचालनालय की आयुक्त का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकटकाल में प्रदेश के अध्यापकों ने बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ अन्य गैर शैक्षणिक कार्य किए हैं। इस कारण अध्यापकों का भी अधिकार बनता था कि उन्हें भी यह लाभ मिलना चाहिए।

प्रदेश के दो लाख 37 हजार अध्यापकों को छठवें वेतनमान की तीसरी किस्त मिलेगी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। अध्यापक सवंर्ग को छठवें वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान करने संबंधी आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्तजयश्री कियावत ने अध्यापक संवर्ग को एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश में लिखा है कि अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान के एरियर के लिए एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किस्तों में क्रमश: 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किए जाने के निर्देश दिए गए थे। फिर शासन की ओर से 29 जुलाई 2020 को रोका गया था। फिर से शासन द्वारा 9 दिसंबर को छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश से प्रदेश के दो लाख 37 हजार अध्यापकों को फायदा मिलेगा। एक-एक अध्यापक को करीब 25 से 30 हजार रुपये मिलेगा।

15 माह का सातवें वेतनमान का एरियर बकाया

नए कैडर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में अध्यापक संवर्ग की जुलाई 2018 में नियुक्ति की गई थी। शासन के आदेश पर नए कैडर के तहत अध्यापकों को जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सितंबर 2019 तक का भुगतान अब तक नहीं हुआ। अध्यापकों को सितंबर पेड अक्टूबर 2019 से सातवें वेतनमान के तहत एरियर का नकद भुगतान किया गया।

शासकीय अध्यापक संगठन की मांग पर शिक्षा विभाग ने छठवें वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन को सातवें वेतनमान का 15 माह का एरियर भुगतान करने के आदेश भी जारी करना चाहिए।

उपेंद्र कौशल, प्रदेश संयोजक, शासकीय अध्यापक संगठन

स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में सिर्फ टीसी व माइग्रेशन जरूरी

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को सिर्फ स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) और माइग्रेशन का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। यह आदेश प्रदेश के सभी कॉलेजों को भेज दिए गए हैं।

दरअसल, ये शिकायतें मिली थीं कि कॉलेजों में विद्यार्थियों से अन्य प्रमाण पत्र (आय-जाति आदि) भी मांगे जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। विभाग की ओर से कहा गया है कि दो दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों ने अन्य प्रमाण पत्र पहले की कक्षाओं में जमा किए हैं। यह भी सुविधा दी गई है कि जिनके पास टीसी और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं हैं, वे शपथ पत्र देकर एक माह में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

लाखों विद्यार्थियों का प्रवेश करना है सुनिश्चित : 19 दिसंबर तक प्रदेश के पांच लाख 61 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। यही अंतिम तारीख टीसी और माइग्रेशन जमा करने की भी है। इन्हें जमा करने पर ही उनका प्रवेश सुनिश्चत हो जाएगा। विद्यार्थियों की शिकायत थी कि कॉलेजों की ओर से जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे

उच्च शिक्षा

- **अन्य दस्तावेज मांगने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश**
- **टीसी व माइग्रेशन नहीं होने पर शपथ पत्र देने की रहेगी छूट**

हैं, उन्हें बनवाने में समय लग रहा है। प्रवेश की अंतिम तारीख नजदीक होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन शिकायतों पर सभी प्राचार्यों के लिए निर्देश जारी किए और इस पर अमल सुनिश्चित करने को कहा।

> आदेश भेज दिया है
> सभी कॉलेजों को टीसी और माइग्रेशन के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी आदेश भेज दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। विद्यार्थी शपथ पत्र देकर एक माह का अतिरिक्त समय ले सकते हैं।
>
> **-चंद्रशेखर बिलम्बे**, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर डीपीआई कमिश्नर से की मुलाकात

स्कूल खोलने पर अभिभावक और संचालक आमने-सामने

1 से 11 तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने की मांग

सच रिपोर्टर ।। भोपाल

प्राइवेट स्कूल संचालकों की स्कूल खोलने की मांग के बाद अब पालक महासंघ इसके विरोध में उतर गया है। पालक महासंघ के पदाधिकारियों ने 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने और कक्षा 1 से 11वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने की मांग की है। अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर संघ ने आज लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर जयश्री कियावत से मुलाकात की। पालक महासंघ का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब भी भोपाल और इंदौर में भयावह बनी हुई है। ऐसे में यदि इस समय स्कूल खोले जाते हैं तो छात्र-छात्राओं की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।

स्कूल खोले तो अभिभावक करेंगे आंदोलन

वैसे भी इस साल कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल अब तक बंद हैं। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो सकी है। दो माह स्कूल लगाकर विद्यार्थियों को कौन सा बड़ा फायदा हो जाएगा। सरकार को इस समय सिर्फ 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने और परीक्षा लेने के आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि 12वीं कक्षा के आधार पर ही मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। 1 से 11वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। पालक महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो वे आंदोलन करेंगे। मालूम हो कि स्कूल खोलने को लेकर सरकार का कोई स्पष्ट आदेश न होने से नाराज प्राइवेट स्कूल संचालकों ने दो दिन पहले आंदोलन का ऐलान किया था। उन्होंने स्कूल नहीं खोलने के आदेश जारी न करने पर ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सामूहिक घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को पांच दिन की मोहलत दी गई थी।

एसोसिएशन ऑफ अन-एडिड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की कमिश्नर जयश्री कियावत से मुलाकात की थी। कमिश्नर कियावत ने जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हुए अगले सप्ताह से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने की बात कही है।

इस साल कोरोना संक्रमण के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो सकी है, इसलिए सरकार को कक्षा 1 से 11वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देना चाहिए। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं अभी बंद रखी जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।

कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष, लोक शिक्षण संचालनालय

यदि अभिभावक ही बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन पालक संघ की जगह यह फैसला खुद अभिभावकों का होना चाहिए। जनरल प्रमोशन बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाए। कोरोना के कारण पहले ही पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है। हम लोगों ने सेशन को आगे बढ़ाने की मांग की है। मार्च की बजाय मई में परीक्षा कराने की मांग की गई। इससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई कवर हो सकेगी।

बाबू थॉमस, सचिव, एसोसिएशन ऑफ अन-एडिड प्राइवेट स्कूल, मध्य प्रदेश

महाविद्यालय में दस्तावेज जमा करने की तारीख में वृद्धि

भोपाल। ऑनलाईन ई-प्रवेश समय सारणी सत्र 2020-21 सीएलसी पंचम चरण के परिप्रेक्ष्य में टीसी, माईग्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालयों में जमा करने की तिथि में 24 नवंबर से वृद्धि करते हुए 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस आशय की जानकारी अग्रणी महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्य ने सभी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अर्द्धशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र के माध्यम से दी है।

आज का इतिहास

1964 मैथिलीशरण गुप्त, राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध हिन्दी कवि का निधन हुआ।

2005 रामानन्द सागर - प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा ख्यातिप्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता का निधन हुआ।

2012 नित्यानंद स्वामी - उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का निधन हुआ।

1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई।

1992 हैदराबाद के हुसैन सागर झील में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई।

1996 भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगाजल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए।

2001 भारत ने नेपाल को दो चीता हैलीकॉप्टर और हथियार दिये।